कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) देश के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर व्यापक सर्वेक्षण के अभाव में, तटवर्ती भूमि के खारेपन की सही सीमा और प्रत्येक वर्ष यह किस सीमा तक फैला रहा है, इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति के अनुमानों सहित विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि आठ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में बलुई मिट्टी सहित मिश्रित खारेपन की समस्या मौजूद है । इस प्रकार की समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मृदा संरचना, मृदा प्रतिक्रिया, बिजली चालकता वर्षा के साथ साथ प्रभावी लवण भूमि जल के स्तरों विविधता, नदी प्रवाह तथा ज्वार भाटा आदि ऐसे मानदण्डों पर विचार किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) तटवर्ती भूमि के खारेपन की समस्याएं विभिन्न भागों में अलग-अलग होती है । तथापि, पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने इस प्रकार के समस्या वाले क्षेत्रों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया है । इन क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए पैकेज की प्रौद्योगिकी में ये शामिल हैं –समुद्री जल प्लावन से बांध बनाकर रक्षा करना, ताजे पानी से लवणों को साफ करना, अल्पकालीन धान तथा रबी की फसलें शुरू करके सस्य पद्धति में सुधार करना, खारे पानी में मछली पालन शुरू करना, धान के साथ झींगा मछली पालना, मिट्टी के घुलकर बहने से रोकने के लिए संशोधित प्रयोग, भूमिगत जल का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना, ताजे जल का अत्यधिक प्रयोग, नारियल, अमरूद, आदि जैसे फलदार वृक्ष तथा कैसुवाइना आदि जैसी वन प्रजातियां उगाना ।

अब तक सीमित प्रयास किए गए है और विभिन्न स्थल परिस्थितियों के अनुकूल पैकेज की अधिक उपयुक्त पद्धतियां भी विकसित की जा रही हैं । लवणीय भूमि का सुधार तथा उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है । समस्या वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण और एक समेकित तरीके से पुनःस्थापन तथा विकास संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना तैयार की गई है । यदि संसाधनों की स्थिति अनुकूल रही तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

Development of Rohini

2549. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of dwelling units in Rohini in Delhi;

(b) whether the Delhi Development Authority in coordination with other concerned authorities have formulated a comprehensive plan for the development of Rohini and other adjoining areas;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) by when Rohini is likely to be fully developed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Rohini Project has a provision for 1,70,000 dwelling units.

(b) Yes, Sir.

(c) All the services network such as water supply, sewerage, electricity and drainage were worked out in consultation with M.C.D., D.E.S.U. and Flood Department of Delhi Administration. Its urban form has been got cleared from DUAC.

(d) In about 3 years after all the schemes are finally approved.